भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-608

दिनांक 28 नवंबर, 2024 को उत्तरार्थ

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण

608. श्री छोटेलालः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ब्लॉक कोन के अंतर्गत बरमौरी, चकरिया, पिंडारी, बासुवारी आदि गांवों में, ब्लॉक नगवा के अंतर्गत गांव खोरैला, महुली, चरगरा, मडापा, देवहर दरेवा, नौडीहा, कोडई, बरवारी, नगवां, शूरशोट दारमा, डुमरकोंन आदि गांवों में और ब्लॉक चोपन के अंतर्गत गांव जोगैल, बहतरटोला, कुलडोमोरी, सत्तरटोला पनारी, लगभग पचासटोला आदि गांवों में विद्युत की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त गांवों में विद्युतीकरण हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) कार्यान्वित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना कार्यों को सुदृढ़ीकरण० एवं संवर्धन सहित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। इस स्कीम के तहत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। यह स्कीम दिनांक 31-03-2022 को बंद हो गई है।

भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। स्कीम के तहत अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 2.77 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। इसमें सौभाग्य के तहत छूटे हुए घरों का विद्युतीकरण और पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जुगा) के तहत स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी चिन्हित किए गए आदिवासी घरों का विद्युतीकरण शामिल है।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीयूवीवीएनएल) की रिपोर्ट के अनुसार:

1. डुमरकोन को छोड़कर कोने, नगवा और चोपन ब्लॉक के उक्त 20 गांव सोनभद्र जिले, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जो पहले से ही विद्युतीकृत हैं और उन्हें औसतन 17:45 घंटे विद्युत की आपूर्ति प्राप्त होती है।
2. इसके अलावा, दो विषयगत गांवों में 02 नव विकसित बस्तियों के छूटे हुए घरों के विद्युतीकरण के लिए आरडीएसएस के तहत 27.90 लाख रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं।

डुमरकोन गांव बिहार राज्य में दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) के अधिकार क्षेत्र में आता है। एसबीपीडीसीएल की रिपोर्ट के अनुसार, डुमरकोन गांव कैमूर जिले के जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में आता है, जहां ऑफ-ग्रिड (सौर ऊर्जा) आधारित प्रणाली के माध्यम से 6-8 घंटे विद्युत की आपूर्ति होती है। इसके अलावा, आरडीएसएस के तहत 68.66 लाख रुपये के ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्यों को संस्वीकृति दी गई है, जिससे गांव में विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा।

****